

एफटीए की निकलेगी राह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर, 2015 में होने वाली पहली ब्रिटेन यात्रा में जैसे तो कई आर्थिक मुद्दे उठेंगे, लेकिन भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते इसमें काफी अहम रह सकता है। भारत में राजग सरकार के आने के बाद यह पहला मौका होगा, जब दोनों देश लंबित आर्थिक मुद्दों पर आगे बढ़ने की पहल करेंगे। ऐसे में एफटीए की अटकली हुई गाड़ी को फिर आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से स्पष्ट संकेत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन पहले भी ईयू के साथ भारत के एफटीए का बहुत बड़ा समर्थक रहा है।

जुलाई, 2015 में यूरोपीय संघ ने 700 से ज्यादा भारत निर्मित दवाओं के आयात पर प्राबन्दी लगाने का फैसला किया था। इसके जवाब में भारत में यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर प्रस्तावित बातचीत को खारिज कर दिया था। उसके बाद मोदी यूरोप की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले शीर्ष नेता हैं। ऐसे में भारतीय पक्ष ही एफटीए का मुद्दा उठाना चाहता है। इसके लिए ब्रिटेन की मदद लेने में कोई हिचक नहीं है। भारत व ईयू के बीच वर्ष 2007 से ही मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत का दौर शुरू हुआ था। कुल 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन गई थी। हालांकि, मोदी सरकार के आने के बाद अभी तक बातचीत का दौर शुरू नहीं हो पाया है।

सूत्रों के मुताबिक यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए को लेकर कितना उत्साहित है। ब्रिटेन की मंशा है कि अगर भारत और ईयू के बीच

बढ़ेगी अटकली गाड़ी

- ♦ मोदी की ब्रिटेन यात्रा में भी उठेगा मुक्त व्यापार समझौते मुद्दा
- ♦ ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए को लेकर खासा उत्साहित

एफटीए को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाती है तो फिर द्विपक्षीय स्तर पर ही एफटीए को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन स्वयं भारत के साथ एफटीए के समर्थक हैं। पिछली बार जब वह भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने यह मंशा जताई थी कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से बात होनी चाहिए। माना जा रहा है कि मोदी के सामने ब्रिटिश पीएम इस मुद्दे को फिर उठाएंगे।

क्या होता है एफटीए

एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते दो या देशों अथवा दो या ज्यादा देशों के संगठनों के बीच किया गया करार है, जिसमें वे एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार की राह की तमाम बाधाओं को दूर करते हैं। मसलन, एक दूसरे के यहां से होने वाले आयातित वस्तुओं पर शुल्क की दर कम कर देते हैं या उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की अनुमति देते हैं। वैसे भारत का उद्योग जगत यूरोपीय संघ के साथ होने वाले एफटीए को लेकर खासा चिंतित है।